



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21052020-219499
CG-DL-E-21052020-219499

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 128]	नई दिल्ली, बुध्स्पतिवार, मई 21, 2020/वैशाख 31, 1942
No. 128]	NEW DELHI, THURSDAY, MAY 21, 2020/VAISAKHA 31, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2020

प्रकरण संख्या: एडीडी-(ओ आई) 13/2020

विषय: चीन जन.गण., इंडोनेशिया, कोरिया गण. और थाइलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "थैलिक एनहाइड्राइड" (पी ए एन) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत ।

फा. सं. 6/16/2020-डीजीटीआर.— 1. मै. आईजी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, मै. थिरूमलाई कैमिकल्स लिमिटेड और मै. एसआई ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिन्हें यहां आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जन.गण., इंडोनेशिया, कोरिया गण., चीनी ताइपेई और थाइलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "थैलिक एनहाइड्राइड" जिसे पी ए एन के रूप में भी जाना जाता है (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद या पीयूसी भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में मूल पाटनरोधी जांच का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि उक्त देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु का पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति हो रही है और उक्त देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू करने का अनुरोध किया है।

संबद्ध देश

3. आवेदकों ने दावा किया है कि चीन जन.गण., इंडोनेशिया, कोरिया गण., चीनी ताइपेई तथा थाइलैंड से पाटित आयातों के कारण क्षति हुई है। तथापि, प्राधिकारी के विश्लेषण के अनुसार चीनी ताइपेई से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो रही है। तदनुसार, वर्तमान जांच के लिए संबद्ध देश चीन जन.गण., इंडोनेशिया, कोरिया गण. और थाइलैंड हैं।

विचाराधीन उत्पाद

4. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद “थैलिक एनहाइड्राइड” (पीएएन) है। “थैलिक एनहाइड्राइड” (पीएएन) थैलिक एसिड का एक एनहाइड्राइड है तथा इसे आर्थो-जाइलीन या नेपथलीन के केटोलेटिक ऑक्सीडेशन द्वारा वाणिज्यिक रूप से उत्पादित किया जाता है। यह रंगहीन, ठोस होता है जिसे विभिन्न रूप से थैलिक एनहाइड्राइड फ्लेक, थैलिक एनहाइड्राइड (98 प्रतिशत न्यूनतम), थैलिक एसिड एनहाइड्रस, थैलिक एनहाइड्राइड (99.8 प्रतिशत न्यूनतम) आदि के रूप में जाना जाता है। थैलिक एनहाइड्राइड के विनिर्देशनों में इसका भौतिक रूप ठोस फ्लेकों का रंग, पिघले हुए उत्पाद का रंग, ठोसीकरण बिन्दु, भार के अनुसार थैलिक एनहाइड्राइड की मात्रा, भार और अमलता इन्डैक्स के अनुसार अन्य एनहाइड्राइड और कार्बनिक अशुद्धताओं की मात्रा शामिल है।
5. विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अध्याय-29 में एच एस कोड 29 और उपशीर्ष 29173500 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और इस जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

6. आवेदकों ने दावा किया है कि भारत में पाटित की जा रही संबद्ध वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के समान है। पाटित आयातों और घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध वस्तुओं के बीच तकनीकी विनिर्देशनों, गुणवत्ता, कार्य या अंतिम प्रयोग की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं तथा इसलिए नियमावली के अंतर्गत इन्हें समान वस्तु माना जाना चाहिए। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

7. यह आवेदन मै. आईजी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, मै. थिरूमलाई कैमिकल्स लिमिटेड तथा मै. एसआई ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों ने दावा किया है कि उन्होंने न तो संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक या भारत में संबद्ध वस्तु के किसी आयातक से संबंधित हैं। आवेदकों का उत्पादन भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है। रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक नियम 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग हैं और आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

कथित पाटन के लिए आधार

1. चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

8. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन.गण को गैर बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-1 के पैराग्राफ-7 के अनुसार किया जाना चाहिए। आवेदक ने चीन के

एक्सेशन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) का उल्लेख किया है और उस पर भरोसा किया है और यह बताया है कि चीन के उत्पादकों को यह दर्शाने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं मौजूद हैं। आवेदक ने दावा किया है कि चीन की घरेलू लागत और कीमतों को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक चीन के निर्यातक बाजार अर्थव्यवस्था के परीक्षण को पास न कर लें। आवेदक ने यह बताया है कि चीन के लिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। उपर्युक्त गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की मान्यता के मद्देनजर और चीन से प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा उसके खंडन के अधीन चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 के अनुसार अनुमानित किया गया है।

ii. इंडोनेशिया तथा थाइलैंड के लिए सामान्य मूल्य

9. इंडोनेशिया तथा थाइलैंड के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ आवेदकों ने दावा किया है कि वे तीनों देशों में संबद्ध वस्तु की कीमतों से संबंधित सूचना लाने में असमर्थ रहे हैं। अतः सामान्य मूल्य का अनुमान कच्ची सामग्री की लागत (प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार खपत कारक और कच्ची सामग्रियों की कीमत के प्रयोग द्वारा), परिवर्तन लागत और बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा लाभ के लिए तर्कसंगत जोड़ के साथ, के अनुमानों पर विचार करते हुए इन देशों में उत्पादन लागत के आधार पर लगाया गया है।

iii. कोरिया गण. के लिए सामान्य मूल्य

10. आवेदकों ने बताया है कि कोरिया गण. के लिए सामान्य मूल्य सार्वजनिक सूचना के अभाव में घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अतः सामान्य मूल्य का परिकलन कच्ची सामग्री की लागत (कोरिया गण. के सीमाशुल्क आंकड़ों के अनुसार वहां से निर्यात कीमत पर खपत कारक और कच्ची सामग्रियों की कीमत के प्रयोग द्वारा), परिवर्तन लागत और बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा लाभ के लिए तर्कसंगत जोड़ के साथ, के अनुमानों पर विचार करते हुए कोरिया गणराज्य में उत्पादन लागत के आधार पर किया गया है।

निर्यात कीमत

11. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के लिए निर्यात कीमत का परिकलन वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) से प्राप्त सौदावार आयात आंकड़ों के आधार पर किया है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार और पत्तन व्यय के लिए समायोजन किए गए हैं।

पाटन मार्जिन

12. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की गई है जिससे संबद्ध देशों से पीयूसी के संबंध में सकारात्मक पाटन मार्जिन प्रदर्शित होता है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पी यू सी का पाटन किया जा रहा है।

क्षति और कारणात्मक संबंध

13. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन हेतु विचार किया गया है। आवेदकों ने समग्र रूप से और भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से पाटित आयातों की बढ़ी हुई मात्रा और कीमत ह्रास के रूप में कथित पाटन के परिणामस्वरूप क्षति के होने के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आवेदकों ने दावा किया है कि उनका कार्य निष्पादन लाभ, नियोजित पूंजी पर आय और नकद प्रवाह के संबंध में बुरी तरह से प्रभावित हुआ है तथा नकद प्रवाह में गिरावट आई है जिसका कारण घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और क्षतिरहित कीमत से कम कीमत पर संबद्ध वस्तु के आयातों में वृद्धि होना है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।

पाटनरोधी जांच की शुरुआत

14. आवेदकों द्वारा विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और आवेदक द्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद और नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, जांच की शुरुआत करते हैं।

जांच की अवधि (पीओआई)

15. आवेदकों ने जुलाई, 2019 से दिसंबर, 2019 (6 महीने) की जांच अवधि का प्रस्ताव किया है।
16. तथापि, जांच अवधि के संबंध में संशोधित नियम 22 (3) के स्पष्टीकरण में निम्नानुसार बताया गया है :

इन नियमों के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि- (i) जांच की शुरुआत की तारीख की स्थिति के अनुसार 6 महीने से अधिक नहीं विगत नहीं होगी, (ii) 12 महीने की अवधि के लिए होगी और जिसके कारण लिखित रूप में रिकॉर्ड किए जाएंगे कि निर्दिष्ट प्राधिकारी न्यूनतम छह महीने की या अधिकतम अठारह महीने की अवधि पर विचार कर सकते हैं।”

17. नियमावली में उपर्युक्त प्रावधान के मद्देनजर वर्तमान जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई जांच अवधि (पीओआई) 01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च 2020 (12 महीने) की है और क्षति अवधि में अप्रैल 2016- मार्च, 2017, अप्रैल, 2017-मार्च, 2018, अप्रैल, 2018-मार्च, 2019 और पी ओ आई की अवधियां शामिल होंगी।

प्रक्रिया

18. नियमावली के नियम 6 में यथाप्रदत्त सिद्धांतों का वर्तमान जांच में पालन किया जाएगा।

सूचना प्रस्तुत करना

19. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पत्तों adg12-dgtr@gov.in तथा adv12-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए।
20. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।
21. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
22. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

समय-सीमा

23. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ईमेल पत्तों adg12-dgtr@gov.in तथा adv12-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने की तारीख या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर

प्राप्त हुआ माना जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

24. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

25. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी की गई व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।
26. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
27. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
28. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
29. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
30. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
31. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
32. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

33. नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं। इलैक्ट्रॉनिक रूप में सार्वजनिक फाइल को रखे जाने के तौर तरीके तैयार किए जा रहे हैं।

असहयोग

34. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

भूपिन्दर एस. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General Of Trade Remedies)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May, 2020

Case No. ADD-(OI)-13/2020

Sub: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of Phthalic Anhydride (PAN) originating in or exported from China PR, Indonesia, Korea RP and Thailand.

F. No. 6/16/2020-DGTR.—M/s. IG Petrochemicals Limited, M/s. Thirumalai Chemicals Ltd. and M/s SI Group India Pvt. Ltd., (hereinafter also referred to as “Applicants”) have filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”) in accordance with Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (herein referred to as the “Act”) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the “Rules”) for original Anti-dumping investigation on imports of “Phthalic Anhydride” also known as PAN (hereinafter referred to as “subject goods” or “product under consideration” or “PUC”) originating in or exported from China PR, Indonesia, Korea RP, Chinese Taipei and Thailand.

2. The Applicants have alleged dumping of the subject goods, originating in or exported from the said countries and consequent injury to the domestic industry, and have requested for imposition of the anti-dumping duties on the import of the subject goods originating in or exported from the said countries.

Subject Countries

3. The Applicants have claimed injury due to dumped imports from China PR, Indonesia, Korea RP, Chinese Taipei and Thailand. However, the Authority’s analysis does not indicate any injury to the domestic industry due to imports from Chinese Taipei. Accordingly, the subject countries for the present investigation shall be China PR, Indonesia, Korea RP and Thailand.

Product under consideration

4. The product under consideration in the present application is “Phthalic Anhydride” (PAN). Phthalic Anhydride (PAN) is an anhydride of Phthalic Acid and is commercially produced by catalytic oxidation of Ortho-xylene or Naphthalene. It is a colorless solid, variously referred as Phthalic Anhydride flakes, Phthalic Anhydride (98% min.), Phthalic Acid Anhydrous, Phthalic Anhydride (99.8% min), etc. Specifications of Phthalic Anhydride includes its physical appearance, color of solid flakes, color of molten product, solidification point, Phthalic Anhydride content by weight, other anhydrides & organic impurities’ content by weight and acidity index.
5. The product under consideration is classified under chapter 29 of Customs Tariff Act, 1975 and subheading 29173500. The custom classification is indicative only and not binding on the scope of the investigation

Like Article

6. The Applicants have claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced subject goods. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as ‘like article’ under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the Applicants in India are being treated as ‘Like Article’ to the subject goods being imported from the subject countries.

Domestic industry & Standing

7. The application has been filed by M/s IG Petrochemicals Limited, M/s Thirumalai Chemicals Ltd. and M/s. SI Group India Pvt. Ltd. The Applicants have claimed that they have neither imported the subject goods from the subject countries nor are related to any exporter or producer of subject goods in the subject countries or any importer of the subject goods in India. The Applicants accounts for major proportion of domestic production in India. On the basis of the information on record, the Authority notes that the Applicants constitute eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b) and the application fulfills the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

Basis for Alleged Dumping**i. Normal value for China PR**

8. The Applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and the normal value should be determined in terms of paragraph-7 of Annexure I of the Rules. The Applicant has cited and relied upon Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol and stated that the Chinese producers should be directed to show that market economy conditions prevail in the industry producing the subject goods. The Applicant has claimed that Chinese domestic costs and prices cannot be accepted unless the Chinese exporters pass the tests of market economy. The Applicant has stated that for China, normal value should be determined in accordance with para-7 and 8 of Annexure I of the Rules. In view of the above non-market economy presumption and subject to rebuttal of the same by the responding exporters from China, normal value of the Subject Goods in China PR has been estimated in terms of Para 7 of Annexure 1 to the Rules.

ii. Normal value for Indonesia and Thailand

9. For the purpose of determining the normal value for Indonesia and Thailand, the Applicants have claimed that they were unable to fetch information relating to the prices of the subject goods in the three countries. Therefore, the normal value has been estimated on the basis of cost of production in these countries considering estimates of raw material costs (using consumption factor and price of raw materials as per published reports), conversion cost and selling, general and administrative expenses, along with reasonable addition for profit.

iii. Normal value for Korea RP

10. The Applicants have stated that normal value of Korea RP could not be determined based on domestic selling price for want of public information. Therefore, the normal value has been constructed on the basis of estimates of cost of production in Korea RP, considering estimates of raw material costs (using consumption factor and price of raw materials at export prices from Korea RP as per its customs data), conversion costs and selling, general and administrative expenses, along with reasonable addition for profit.

Export Price

11. The Authority has computed the export price for the subject countries based on the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) transaction-wise import data. Adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, commission, bank charges and port expenses.

Dumping Margin

12. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which shows positive dumping margin in respect of the PUC from the subject countries. There is sufficient prima facie evidence that the PUC are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries.

Injury and Causal Link

13. Information furnished by the Applicants has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The Applicants have furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption in India, and price suppression. The Applicants have claimed that their performance has been adversely impacted in respect of profits, return on capital employed, and cash flow, as a result of increase in imports of subject goods at a price below the selling price and non-injurious price of the domestic industry. There is sufficient prima facie evidence of injury being suffered by domestic industry caused by dumped imports from subject countries.

Initiation of Anti-Dumping Investigation

14. On the basis of the duly substantiated written application by the Applicants, and having satisfied itself, on the basis of prima facie evidence submitted by the applicant, about dumping of the product under consideration

originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury and in accordance with the Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the product under consideration originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would remove the injury to the domestic industry.

Period of Investigation (POI)

15. The Applicants have proposed the period of investigation from July, 2019 to December, 2019 (6 months).
16. However, the explanation to amended Rule 22(3) with regard to the period of investigation states as under:

For the purposes of these rules, the period of investigation shall,- (i) not be more than six months old as on the date of initiation of investigation. (ii) be for a period of twelve months and for the reasons to be recorded in writing the designated authority may consider a minimum of six months or maximum of eighteen months."

17. In view of the above provision in the Rules, the period of investigation (POI) adopted by the Authority for the present investigation is 01st April, 2019 to 31st March, 2020 (12 months) and the injury period will cover the periods April 2016- March 2017, April 2017-March 2018, April 2018- March 2019 and the POI.

Procedure

18. Principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation.

Submissions of Information

19. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg12-dgtr@gov.in and adv12-dgtr@gov.in
20. The known producers/exporters in the subject countries, their governments through their embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
21. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.
22. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to other interested parties.

Time Limit

23. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg12-dgtr@gov.in and adv12-dgtr@gov.in within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
24. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

Submission of information on confidential basis

25. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.
26. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.
27. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to

inspect such submissions.

28. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
29. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
30. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
31. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
32. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

33. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. The modality of maintaining public file in electronic mode is being worked out.

Non-cooperation

34. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

BHUPINDER S. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority